



यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर: भारत के नरियात पर प्रभाव

यह एडिटरियल 22/10/2023 को 'हट्टि बिजनेसलाइन' में प्रकाशित ["India must strategise against EU carbon tax"](#) लेख पर आधारित है। इसमें भारत की नरियात और जलवायु नीति के लिये यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) के नहितार्थ के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलमिस के लिये:

यूरोपीय संघ, कार्बन ट्रेड, कार्बन उत्सर्जन, यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS), हरति ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन, मुक्त व्यापार समझौता (FTA), साझा कति वभिदति उत्तरदायित्व

मेन्स के लिये:

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और भारत पर इसके प्रभाव।

वशिषज्जों का मानना है कि यूरोपीय संघ (EU) द्वारा कार्बन सीमा कर (Carbon Border Tax- CBT) संग्रहण की योजना (1 जनवरी, 2026 से प्रभावी) भारत की नरियात लागत को बढ़ा सकती है। अक्टूबर 2023 से भारतीय नरियातकों को लगभग प्रत्येक दो माह पर अपनी प्रकरियाओं के संबंध में दस्तावेज जमा करने होंगे। यूरोपीय संघ के पास जल्द ही भारतीय नरियातकों की प्रकरियाओं पर पेश दस्तावेज की जाँच करने के लिये 'सत्यापनकर्ता' (verifiers) होंगे। वर्तमान में यह केवल इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बजिली पर लागू होता है, लेकिन भविष्य में इसे यूरोपीय संघ में सभी आयातों तक वसितारति किया जाएगा।

EU का 'कार्बन सीमा कर' क्या है?

- EU का कार्बन सीमा कर (CBT) या कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) एक नीतगित उपाय है जिसका उद्देश्य EU में आयातित कुछ वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन पर उचित मूल्य अधिरोपित करना है।
- यह 'फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज' (Fit for 55 in 2030 package) का एक भाग है, जो यूरोपीय जलवायु कानून के अनुपालन में वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम से कम 55% तक कम करने की यूरोपीय संघ की एक योजना है।
- CBAM उन देशों से सीमेंट, लौह एवं इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बजिली और हाइड्रोजन के आयात पर लागू होगा जिनकी जलवायु नीतियाँ यूरोपीय संघ की तुलना में कम कठोर हैं।
 - इन वस्तुओं के आयातकों को कार्बन प्रमाणपत्र (carbon certificates) की खरीद करनी होगी जो उनके उत्पादों में नहित कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को दर्शाएँगे।
 - इन प्रमाणपत्रों का मूल्य EU उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU Emissions Trading System- ETS) में कार्बन के मूल्य के बराबर होगा। ETS एक बाजार-आधारित प्रणाली है जो EU के भीतर उद्योगों के उत्सर्जन को नयित्तरति करती है।
- इसका उद्देश्य गैर-EU देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना और कार्बन लीकेज को रोकना है, जो नमिन पर्यावरणीय मानकों वाले देशों में कार्बन-सघन गतिविधियों का स्थानांतरण है।

CBAM को लेकर भारत की चिंताएँ

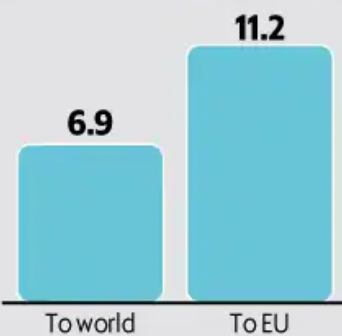
- लागत की वृद्धि और प्रतस्पर्द्धात्मकता की कमी: CBAM लागत में वृद्धि कर सकता है और यूरोपीय संघ को भारतीय नरियात की प्रतस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकता है, विशेष रूप से इस्पात एवं एल्यूमीनियम जैसे कषेत्रों में, जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा भाग है।
 - एक रपिर्ट के अनुसार, CBAM 1 जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ में चुनदा आयात पर 20-35% कर/टैक्स के रूप में अभिविकृत होगा।
 - भारत के लौह अयस्क पेलेट्स, लौह, इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों के नरियात का 26.6% यूरोपीय संघ को जाता है।
 - ये उत्पाद CBAM से प्रभावित होंगे। भारत EU को सालाना लगभग 8 बलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के माल का नरियात करता है।

- **अनुपालन संबंधी मुद्दे:** CBAM अनुपालन के दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है। यह भारतीय उत्पादकों और आयातकों के लिये प्रशासनिक एवं तकनीकी चुनौतियाँ भी पैदा कर सकता है, जनिहें यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप अपने **उत्सर्जन की नगिरानी, गणना, रपिर्ट एवं सत्यापन** की आवश्यकता होगी।
 - भारत की छोटी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कविर्ष 2006 में भी हुआ था जब यूरोपीय संघ ने रासायनिक आयात को वनियमिति करने के लिये एक कठोर व्यवस्था (EU REACH) लागू की थी।
- **FTA मानदंडों के वरिद्ध:** CBAM की एक 'नॉन-टैरफि बैरियर' के रूप में आलोचना की जा रही है जो शून्य शुल्क **FTAs** की अवहेलना करती है। भारत लेवी का भुगतान करता है, जबकि कथिति 'हरति' उत्पादों के लिये शुल्क-मुक्त प्रवेश की अनुमतति देता है, जिसे वरिधाभासी स्थिति के रूप में देखा जा रहा है।

RISING TENSION

The proposed tax has raised concerns among Indian metal producers, who fear it will create a new trade barrier for exports to Europe.

Share (%) of CBAM products in India's exports



India's total exports of CBAM products to EU:

\$8.22 bn

Impact on sectors covered under CBAM

mint

↑ HIGH

	Number of tariff lines affected	EU's share (%) in India's exports of CBAM products
Iron ore, concentrates	16	19.9
Steel products	163	20
Iron and steel	473	31.4
Aluminium and products	85	27.7

↓ LOW

Cement	14	6.1
Fertilizer	24	0.7
Hydrogen	1	0
Electrical energy	1	0

CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

- **हरति संक्रमण के प्रतियूरोपीय संघ और वकिसति देशों की प्रतबिद्धता के वपिरीत:** आयात पर कार्बन कर का अधरिपण—जो प्रलेखति कार्बन उत्सर्जन द्वारा नरिधारति होता है, अन्य देशों के हरति संक्रमण (Green Transition) का समर्थन करने के यूरोपीय संघ और वकिसति देशों की प्रतबिद्धता के वपिरीत है। हरति संक्रमण के समर्थन के बजाय इसके परणामस्वरूप वपिरीत दशिा में धन का प्रवाह होगा।

भारत को EU के CBAM के प्रतकिसि प्रकार प्रतकिरिया देनी चाहिये?

- बहुपक्षीय मंचों पर CBAM का वरिध: भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर CBAM का वरिध करना चाहिये क्योकियह तंत्र वकिसशील वरिध की औद्योगीकरण की क्षमता को सीमिति कर **'साझा कति वभिदति उत्तरदायतिव' (common but differentiated responsibility)** के सिद्धांत को कमजोर करता है।
- CBAM के अनुरूप नीतियों वकिसति करना: भारत यूरोपीय संघ को अपने नरियात पर CBT जैसा एक कर वसूलने पर वधिार कर रहा है। हालाँकि इसके परणामस्वरूप उत्पादकों पर सदृश कर का बोझ पड़ सकता है, लेकिन एकत्र किये गए धन को उत्पादन प्रक्रियाओं को अधिकि पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिये पुनर्रनिवेश कयिा जा सकता है, जिसे संभाविति रूप से भवषिय के करों को कम कयिा जा सकता है।
 - हालाँकि इस बात को लेकर अनरिश्चितता है कि यूरोपीय संघ इस तरह के कदम को स्वीकार करेगा या नहीं और कया इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वधिकि रूप से प्रश्नगत कयिे बनिा लागू कयिा जा सकता है।
- **नरियात बाज़ारों में वविधिता लाना:** भारत को एशिया, अफ्रीका और लैटनि अमेरिका जैसे कषेत्रों में नए अवसरों की तलाश कर यूरोपीय संघ के बाज़ार पर नरिभरता कम करनी चाहिये। यह एक उपयुक्त रणनीतिक प्रतकिरिया होगी। यह वविधिीकरण देश को CBAM और अन्य आर्थिक परविर्तनों के

प्रभावों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है।

■ **हरति उत्पादन को प्रोत्साहन देना:**

- भारत तैयारी शुरू कर सकता है और वस्तुतः स्वच्छ उत्पादन को प्रोत्साहित कर उत्पादन को हरति एवं संवहनीय बनाने के अवसर का लाभ उठा सकता है। इससे भारत को अधिक कार्बन-सचेत भवषिय में प्रतिसिपर्द्धी बने रहने का अवसर प्राप्त होगा।
- इसके साथ ही, भारत को अपने वकिसात्मक लक्ष्यों और आर्थिक आकांक्षाओं से समझौता कथि बनि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के अनुरूप ढलने और अपने **'2070 शुद्ध शून्य लक्ष्य' (2070 Net Zero Targets)** प्राप्त करने की दशिा में तत्पर बने रहना होगा।

नषिकर्ष

यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर (CBAM) भारत के नरियात के लथि चुनौतथिौ पेश करता है, वशिष रूप से इस्पात एवं एल्यूमीनयिम जैसे कषेत्रों में। भारत को एक बहुआयामी दृष्टकोग की आवश्यकता है जसिमें CBAM का वरौध करने के लथि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रयि होना, द्वपिकषीय समझौतों की तलाश करना, नरियात बाज़ारों में वविधिता लाना और हरति उत्पादन को बढावा देना शामिल है। कार्बन-सचेत वैश्वकि बाज़ार में भारत की स्थति सुदृढ करने के लथि पर्यावरणीय उत्तरदायतिव और आर्थकि समृद्धकि संतुलति करना आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: भारत के लथि यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा कर के नहितार्थों का वशि्लेषण कीजथि और उन रणनीतकि प्रतकिरयिाओं की चर्चा कीजथि जो भारत इन चुनौतथिौ से नषिटने के लथि आजमा सकता है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न 1. नमिनलखति में से कसिने अपने नागरकिों के लथि डेटा संरक्षण (डेटा प्रोटेक्शन) और प्राइवेसी के लथि 'सामान्य डेटा संरक्षण वनियिमन (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन)' नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई, 2018 से कार्यान्वयन शुरू कर दथिा? (2019)

- (a) ऑस्ट्रेलथिा
- (b) कनाडा
- (c) यूरोपीय संघ
- (d) संयुक्त राज्य अमेरकिा

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. 'व्यापक-आधारयुक्त व्यापार और नविश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट एग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत एवं नमिनलखति में से कसि के बीच बातचीत के संदर्भ में दखिाई पढता है। (2017)

- (a) यूरोपीय संघ
- (b) खाड़ी सहयोग परषिद
- (c) आर्थकि सहयोग और वकिसा संगठन
- (d) शंघाई सहयोग संगठन

उत्तर: (a)